

(ख) जी हां। दिल्ली नगर निगम के जरिये मलेरिया-रोधी पर्याप्त दवाइयां दे दी गई हैं।

(ग) मलेरिया-रोधी कार्यकलापों से संबंधित क्षेत्र दिल्ली के लगभग 52,60,000 लोग लाभान्वित होंगे।

‘एक व्यक्ति एक रोजगार’

2627. श्री राम चितास पासवान : क्या संसदीय कार्य तथा भ्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्राथिक विषमता को कम करने और अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के उद्देश्य से सरकार ‘एक व्यक्ति एक रोजगार’ के सिद्धान्त को कानून बना कर लागू करेगी ?

संसदीय कार्य तथा भ्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले अत्याधिक रोजगार अवसरों से बेरोजगारी घटने तथा प्राथिक विषमताओं के कम होने की संभावना है।

तालाबन्दियों और हड़तालें

2628. श्री अनन्त राम जायसवाल :

श्री ए० आर० बड़ोनारायण :

श्री समर गुह :

क्या संसदीय कार्य तथा भ्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून 1978 की अवधि में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में पृथक पृथक कितनी तालाबन्दियां और हड़तालें हुईं तथा 1977 की इसी अवधि के दौरान उनकी संख्या कितनी थी ;

(ख) इन तालाबन्दियों और हड़तालों के कारण कितने मूल्य के औद्योगिक उत्पादन को हानि हुई ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा क्या उन को दूर करने के लिये सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

संसदीय कार्य तथा भ्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1977 और 1978 के वर्षों में जनवरी से मई की अवधि के दौरान उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार किया गया विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [घन्यालय में रखा गया। देखिए संख्या LT० 2560/78] है, जिसमें सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में हड़तालों एवं तालाबन्दियों की संख्या दर्शाई गई है।

(ख) नष्ट हुए उत्पादन के बारे में सम्पूर्ण आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। ।

(ग) 1977 और 1978 के वर्षों में जनवरी से मई की अवधि के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार किया गया विवरण-2 सभा पटल पर रख दिया गया है। [घन्यालय में रखा गया। देखिए संख्या LT 2560/78]। जो सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में तालाबन्दियों एवं हड़तालों के कारण दर्शाता है।

सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और केन्द्र तथा राज्यों में स्थापित औद्योगिक संबंध तंत्र की सहायता से देश में औद्योगिक वातावरण में सुधार करने के सभी प्रयास कर रही है। जहां आवश्यक होता है, वहां समझौता कराने के लिए सरकार विवादों में मध्यस्थता कर रही है।